1	2	3
8.	तरूण भारत संघ, जिला अलवर	64,300/-रुपये
9.	राजस्थान पर्यावरण परिरक्षण समिति जयपुर	75,000/-रुपये
	कुल :	3,46,800/-रुपये

Disputes over Revision of Electoral Rolls

187. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the long-pending disputes over the revisions of electoral rolls have since been resolved;

(b) the nature of the disputes;

(c) what is the attitude of the Central Government in regard to the disputes; and

(d) what steps have so far been taken for the resolution of the disputes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY of LAW AND JUSTICE (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ):(a) to (d) It is not clear which are the disputes referred to. The revision of electoral rolls by the Election Commission is a continuous process. In order to keep the electoral rools up-to-date and in as perfect a condition as possible the Election Commission undertakes an annual revision of the rolls. Well settled procedures laid down by the Election Commission exist for such a revision of electoral rolls and also for rectifying deficiencies which may come to notice through a special revision.

पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

188. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) औरंगाबाद में न्यायपीठ स्थापित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने पुणे में न्यायपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर जोर नहीं दिया है।

कर अपवंचकों का पता लगाने के लिए बम्बई में मारे गए छापे

189. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कर-अपवंचकों और काले धन के जमाखोरों के आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों पर हाल में छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 1989 के महीने के दौरान आयकर विभाग ने बम्बई में 147 तलाशियां लीं। इन

तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथम-दृष्टया 110.76 लाख रु० के मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। उपर्युक्त तलाशियों के दौरान जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी, उन्होंने कुल 550.37 लाख रु० की आय को छिपाने की बात को स्वीकार कर लिया है।

(ग) किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तलाशियों के दौरान गिरफ्तारी के लिए आयकर अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

(घ) प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत सभी मामलों में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Violation of Norms of RBI and NABARD by Various States

190. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE, be pleased to stale:

(a) what are the names of the States which have violated the guidelines and norms of the Reserve Bank of India and NABARD regarding interest on loans to fanners and rescheduling of these loans; and

(b) what steps the Central Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE ' (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) It was noticed by Reserve Bank of India (RBI) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) that some coopexative banks were not fully complying with instructions relating to interest rates, conversion of loans etc. and directives in this regard were violated in 12 States and one Union Territory namely: (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Gujarat, (4) Haryana, (5) Karnataka, (6) Kerala, (7) Madhya Pradesh, (8) Maharashtra, (9) Orissa, (i0) Punjab (11) Tamil Nadu, (12) West Bengal and (13) Union Territory of Pondicherry.

(b) NABARD *vide* its circular dated 29th November, 1988 addressed to the Managing Directors of all State Cooperative Banks and State Land Development Banks, withheld refinance facilities till an undertaking is furnished by the concerned institutions that they would follow the instructions/guidelines issued by the RBI/NABARD.

NABARD has reported that refinance facilities have been resumed in all States, except in Maharashtra, Madhya Pradesh and Pondicherry, since undertakings from the apex banks of these States/Union Territories are still awaited.

दिल्ली में मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाना

191. श्री संतोष बागड़ोदिया: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के सभी चुनाव-क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में संशोधन करने के आदेश दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मतदाता सूचियों के संशोधन सम्बन्धी कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) दिल्ली में 18 वर्ष की आयु के अनुमानत. कितने युवक-युवतियां मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, हां।